ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 2

आम बजट कृषि क्षेत्र के लिये सरकार को क्या करना चाहिये ?

रविवारीय, 19 - 25 जनवरी 2020 वर्ष- एक, अंक-24, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्य 2 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

किसानों के लिए सरकार कृतसंकल्पितःमुख्यमंत्री

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलने आने वाले लोगों से बड़े ही सहजता से मुलाकात की और कहा कि, नई सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। किसानों और युवाओं पर सरकार की खास नजर है। किसान हमारे राज्य और देश की अर्थव्यवस्था रीढ़ हैं। इनकी खुशहाली और विकास के लिए इन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की हमारी कोशिश है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। इन तरीकों को एक्सप्लोर किया जा रहा है, जिससे उन्हें रोजगार उपलब्ध करा सकें। सभी जिलों में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को सुदृढ़ किया जाएगा। इससे युवाओं को इधर उधर न भटकना पड़े।

सोशल मीडिया के जरिए आ रही कई समस्याएं

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए व्यक्तिगत, सामाजिक, रोजगार से संबंधित, स्कूल से संबंधित एवं अन्य कई तरह की समस्याएं हम तक पहुंच रही, जिसके समाधान के लिए हम तत्पर हैं। हमारी सरकार ऐसी व्यवस्था की तैयारी में हैं, जहां अपनी समस्याओं से परेशान लोगों को उसका जल्द से जल्द समाधान मिल सके।

रांची रेल मंडल में कई ट्रेनें देर से आई

21 तारीख को कई ट्रेनें देर से आयीं। इसका मुख्य कारण धुंध रहा। देर से आने वाली ट्रेनों में 18312 मंडुवाडीह - सम्बलपुर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 1 घंटे 22 मिनट देरी से आई वहीं 13352 अल्लापुजा - धनबाद एल्लेपी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 10 मिनट देरी से आई ।20840 नई दिल्ली - राँची राजधानी एक्सप्रेस भी अपने निर्धारित समय से 37 मिनट देरी से आई।

दिवाली दशहरा में मिलावटी और खतरनाक मिठाइयों की जांच के लिये एकत्र किये गये सैंपल का चार महिने बाद आया है रिजल्ट

ऐसी जांच से क्या लाभ?

मुख्य संवाददाता

रांची : बीते साल पर्व त्यौहारों के मौसम में ग्रीन रिवोल्ट ने मिठाईयों के मिलावटी बाजार की खबर प्रकाशित की थी। तब प्रशासन ने दूकानदारों से मिठाइयों का सैंपल लिया था। आज चार महिने बाद उन सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आ रही है। जिसमें ज्यादतर में कमी पाई गयी है जो आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलावाड़ है। लेकिन उससे भी बड़ा खिलवाड़ संबंधित विभाग, अधिकारी कर रहे हैं। आखिर चार महिनें के बाद इस रिपोर्ट का क्या औचित्य है? खतरनाक एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों को बेचने से रोकने में प्रसाशन असफल रहा। आखिर त्वरित जांच और कार्रवाई का एक सिस्टम हम आज तक क्यों नहीं बना पायें हैं? आज ये रिपोर्ट प्रहसन सा लगता है। अब अगर दूकानदारों पर कार्रवाई भी होती है तो उससे दशहरा दिवाली के समय जहरीले और खतरनाक मिठाइयों को खरीद और खा चुके लोगों के स्वास्थ्य की भरपाई कैसे होगी? रिपोर्ट आई है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, रांची ने औचक निरीक्षण कर तब दूकानदारों से सैंपल लिए थे अब हाल में पता चला है कि दशहरा दिवाली के समय दुकानों से लिए गए फूड सैंपल में कमी पाई गई है। कुछ दूकानों के खाद्य पदार्थों में खतरनाक रंगो की मिलावट पकड़ी गयी है। अनुमण्डल पदाधिकारी के इस कार्रवाई से आमजन को क्या लाभ होगा? दिवाली के दौरान उपायुक्त, रांची के निदेशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी, रांची लोकेश मिश्रा ने रांची के विभिन्न मिठाई विक्रेता एवं निर्माताओं के दुकानों से जांच के लिए सैंपल कलेक्ट करवाये थे। उक्त जांच में रांची के तीन विक्रेताओं की मिठाईयों में कमी पाई गई। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात इन दुकानों पर शो कॉज़ नोटिस के साथ आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसएफएल, नामकुम के फ़ूड एनालिस्ट ने त्योहारों के दौरान लिए गए सैंपल की रिपोर्ट अनुमण्डल कार्यालय, रांची के समक्ष पेश की है।

हकीकत में आम दिनों में भी शहर में मिलावटी और खाद्य पदार्थों की बिक्री धड़ल्ले से होती है लेकिन इस पर रोक का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है।

सीसीएल एवं वन पर्यावरण विभाग के बीच हुआ एमओयू

संवाददाता

नई दिल्ली: सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ एक समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुआ । समझौते का उद्देश्य मानव और पोषण के लिए कचनार का पारंपरिक उपयोग संबंधी विज्ञान का अध्ययन एवं झारखंड के मूल आदिवासी समुदायों की मानव आंखों, हृदय संबंधी जीर्ण बीमारियों और मानसिक स्वास्थ्य पर जलती हुई ईंधन लकड़ी और बायोमास खाना पकाने के संबंध का मूल्यांकन करना है। इस अवसर पर प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक एम्स और सह-जांचकर्ता, डॉ. राकेश यादव, कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर, एम्स, डॉ. नंद कुमार प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री, एम्स, डॉ. रामकिशोर साह, वैज्ञानिक, डॉ. आरपी सेंटर, एम्स, डॉ. सुभ्रदीप करमाकर, बायोकैमिस्ट्री के सहायक प्रोफेसर, एम्स, डॉ. अनूप डागा (सदस्य सचिव सीएसआर, एम्स), श्री भोला सिंह, निदेशक (योजना/परियोजना), सीसीएल, सौमित्र सिंह, महाप्रबंधक (ई एंड एफ), सीसीएल, एवं एसएस लाल, मुख्य प्रबंधक (सीएसआर), सीसीएल उपस्थित थे।

वैज्ञानिकों ने बनाया नकली दवाओं से बचाने वाला सुरक्षा टैग

नकली दवाओं का कारोबार दुनिया भर में तेजी से फल-फूल रहा है। अनुमान है कि इसके चलते हर साल फार्मा इंडस्ट्री को करीब 10 फीसदी का नुकसान हो जाता है, जबकि इससे बढ़कर दुनिया भर में हजारों लोग नकली दवाओं के चलते काल के गाल में समां जाते हैं। अब शोधकर्ताओं ने इस समस्या से निपटने का एक और हल खोज निकाला है। उन्होंने एक उन्नत सुरक्षा टैग बनाने में सफलता हासिल की है, जिसे सीधे दवाई में लगा सकते हैं, और उसके साथ ही खाया जा सकता है। इस टैग का मकसद नकली दवाओं की बिक्री को रोकना है। सामान्यतः असली और नकली दवाओं में इतनी समानता होती है, जो आमतौर पर आंखों से दिखाई नहीं देती है। एसोचैम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 25 फीसदी दवाएं नकली या फिर घटिया क्वालिटी की होती हैं। देश में नकली दवाओं का सबसे बड़ा केंद्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, जिसमें दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा शामिल हैं।

मेकॉन में पर्यावरण और देशभक्ति पर दो दिवसीय नाटक उत्सव संपन्न

रांची :मेकॉन लिमिटेड के राजभाषा विभाग व चेतना-सामाजिक समुदाय की ओर से मेकॉन कम्युनिटी हॉल में दो दिवसीय नाटक उत्सव का आयोजन किया गया। पहले दिन के कार्यक्रम की शुरुआत मेकॉन के निदेशक परियोजना सलिल कुमार, निदेशक वित्त आर एच जुनेजा, निदेशक वाणिज्य एस के वर्मा व सीवीओ यू के केडिया ने दीप प्रज्वलित कर की । कार्यक्रम में दिल्ली के प्रसिद्ध थिएटर ग्रुप ''**सुखमंच**'' की शिल्पी मारवाहा की टीम ने नाटक "गगन दमामा बाज्यो" का मंचन किया । देश भक्ति से लबरेज इस नाटक में सुभाषचंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के चरित्र ने दर्शकों के मन पर गहरी छाप छोड़ी । भारत की आजादी की क्रांति पर आधारित इस नाटक ने दर्शकों का मन मोह लिया । दूसरे दिन सीएमडी अतुल भट्ट की अध्यक्षता में सुबह पर्यावरण पर आधारित नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया जिसमें आस्ट्रेलिया के जंगलो में लगी आग पर चिंता जताते हुए पेड़ बचाने, धरती बचाने का आह्वान किया गया । शाम में नाटक "एक द्रोणाचार्य " का मंचन मेकॉन के अधिकारियों ने किया जिसकी सभी ने सराहना की ।

हटिया रेल मण्डल चिकित्सालय में होम्योपैथिक क्लिनिक का शुभारंभ

संवाददाता

रांची : रेल मण्डल चिकित्सालय, हटिया में होमियोपैथी क्लिनिक का उद्घाटन मण्डल रेल प्रबंधक नीरज अम्बष्ठ ने किया। अब तक यहां सिर्फ एलोपथी उपचार की सुविधा थी, अब होम्योपैथिक उपचार की भी सुविधा उपलब्ध हुई है। यह क्लिनिक हर सप्ताह सोमवार से शुक्रवार सुबह 09:30 से दोपहर 01:30 बजे तक खुला रहेगा। क्लिनिक में डॉ रूबी मरीज़ो को देखेंगी। उद्घाटन अवसर पर अपर मण्डल रेल प्रबंधक अजीत सिंह यादव, अपर मण्डल रेल प्रबंधक एम एम पंडित, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जी सी हेम्ब्रोम, वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त महेश्वर सिंह, वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक सह मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी नीरज कुमार, वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी ब्रजेश साहू, मण्डल कार्मिक अधिकारी श्रीनिवास, मेंस काँग्रेस से चंचल सिंह एवं मण्डल के अन्य अधिकारी ,कर्मचारी उपस्थित थे।

रंगीन मछली पालन के महिला लाभुकों के लिये तीन दिवसीय कार्यशाला संपन्न

संवाददाता

रांची :रंगीन मछली पालन के महिला लाभुकों का दुसरे चरण का तीन दिवसीय कार्यशाला 18 दिसंबर से प्रारंभ हुआ जिसका शुभारंभ आशीष कुमार उप मत्स्य निदेशक (जलाशय) झारखंड रांची द्वारा किया गया। कार्यशाला में कुल 25 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यशाला में अशोक कुमार सिंह, सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, रांची एवं रण विजय कुमार, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, अनुसंधान, सुश्री सावन शीला हंस, मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, अनुसंधान के साथ साथ रंगीन मछली के विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे।

उपायुक्त, रांची ने किया गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों का निरीक्षण और कहा

गणतंत्र दिवस को हम सब मिलकर यादगार बनायेंगे

संवाददाता

रांची : गणतंत्र दिवस-2020 के मद्देनजर परेड की तैयारियों के निरीक्षण के लिए उपायुक्त रांची राय महिमापत रे ने मोराबादी मैदान में गणतंत्र दिवस-2020 की तैयारियों के जायजे के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक,रांची, उप विकास आयुक्त, रांची, अनुमंडल पदाधिकारी, रांची के साथ दौरा किया साथ ही सभी परेड पार्टियों के रिहर्सल प्रदर्शन का निरीक्षण किया। परेड निरीक्षण के उपरांत उन्होंने सभी परेड पार्टियों को संबोधित करते हुए परेड बैंड की टुकड़ी को आपसी तालमेल में सुधार करने को कहा और 26 जनवरी को होने वाले परेड के लिए उन्होने सभी को शुभकामनाएं दी।

उपायुक्त ने कहा कि, ''यह हम सभी के लिए गर्व का मौका है। राष्ट्रीय त्योहार के इस दिन को हम सभी को मिलकर यादगार बनाना है।उन्होंने उद्घोषकों को 22 जनवरी, बुधवार से ही परेड की टीमों के साथ रिहर्सल करने का निर्देश दिया। जिससे अंतिम समय में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। परेड निरीक्षण के उपरांत उन्होंने कार्यक्रम स्थल का मुआयना करते हुए अतिथियों एवं आमजनों हेतु आने-जाने के रूट प्लान की जानकारी ली। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, आपातकालीन किट, इत्यादि की सुविधा तैयार रखने के निर्देश दिए।

5 फरवरी को पंचघाघ में मनेगा पर्यटन पर्वः उपायुक्त

सिदाम

खूंटी के पर्यटन स्थलों पर लाखों की संख्या में सपरिवार जुटते हैं सैलानी

खूंटीःआगामी 5 फरवरी को पर्यटन पर्व मनाया जाएगा, इसके लिए खूंटी जिले का प्रसिद्ध पंचघाघ जलप्रपात का चयन किया गया है।

जिले में कई दर्शनीय पर्यटन स्थल हैं जहां दिसंबर से ही लाखों की संख्या में सैलानी सपरिवार पिकनिक का आनंद उठाने आते हैं। खूंटी जिले में पर्यटन स्थलों की भरमार है। दिसंबर का महीना आते ही इन पर्यटन स्थलों में सैलानियों की भीड़ जुटने लगती है और जिले के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों का आना प्रारंभ हो गया है। यहां एक से बढ़कर एक पर्यटन स्थल और फॉल है। इसमें पंचघाघ जल प्रपात, पेरवांघाघ, लटरजंग डैम, रानी फॉल, बाबा आम्रेश्वरधाम, उलिहातू, सोनमेर मंदिर, डोम्बारीबुरु, पेलोल डैम मुख्य रूप से शामिल है। इन पर्यटन स्थलों को प्रकृति ने मानो फुर्सत से गढ़ा है। विशेषकर दिसंबर एवं जनवरी का महीने में हर दिन दूरदराज के इलाकों से पर्यटक पहुंचते है।

प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा पंचघाघ जलप्रपात लाखों की संख्या में पर्यटकों को कर रहा आकर्षित

पंचघाघ जलप्रपात झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है। जो राजधानी से 52 किमी तथा खूंटी जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर रांची-चाईबासा मुख्य मार्ग से डेढ़ किलोमीटर पश्चिम दिशा में स्थित है। पंचघाघ जलप्रपात आसानी से पहुंचा जा सकता हैं। यहां की प्राकृतिक सौंदर्य व मनोरम छटा लोगो को बार-बार आने के लिए आकर्षित करती है। कलकल करती नदी जब गहराई में गिरती है तो वह दृश्य मन को सुकून देती है। साल वृक्षों से घिरे पंचघाघ जलप्रपात बरबस ही लोगो को अपनी ओर खींच लेते है। कुछ साल पूर्व बनाया गया स्वीमिंग पुल पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। साथ ही जलप्रपात समेत आसपास के स्थानों पर लोगों में सेल्फी लेने की होड़ मची रही।

साल के अंतिम माह व नए साल में बड़ी संख्या में सैलानी पर्यटन स्थलों पर पिकनिक मनाने आते हैं। इसलिए सभी पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। पिकनिक मनाने आने वालों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसे ध्यान में रखते हुए आने-जाने वाले मार्गो पर लगातार पुलिस गश्त की जा रही है। छुट्टी वाले दिनों में पिकनिक स्थलों पर विशेष चौकसी रखी जा रही है। हल्की बारिश और ठंड में भी सैलानियों का जोश कम नहीं हुआ है। वहीं पिकनिक को लेकर पर्यटन स्थलों में जिला प्रशासन की ओर से विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। ●

खिलाड़ियों की भी है जिम्मेदारी

ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए खेल जगत को भी कुछ करना होगा।ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में सितंबर से लगी आग से निकलता धुंआ ऑस्ट्रेलियन ओपन की तैयारी पर भी पड़ा था. जंगलों की आग ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि खेल जगत को भी जलवायु परिवर्तन से निपटने योगदान देने की जरूरत है. ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पार्क में सीजन का पहला ग्रैंड स्लैम सोमवार से शुरू हो गया. यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट ऐसे समय में हो रहा है जब ऑस्ट्रेलिया जंगलों में आग की भयानक समस्या से जूझ रहा है. इसकी वजह से जलवायु संरक्षण में खेलों की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है. ऑस्ट्रेलियाई संरक्षण फाउंडेशन (एसीएफ) के जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के मैनेजर गवन मैकफैडजेन ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा, "मुझे पता है कि लोग कहेंगे कि खेल और राजनीति को अलग रखना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है. खेल संगठनों को जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक मुखर होना चाहिए."

कई खिलाड़ियों ने मेलबर्न की वायु गुणवत्ता को लेकर शिकायत की थी. ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग के कारण मेलबर्न और सिडनी समेत कई अन्य शहरों की हवा खासी प्रदूषित हो गई है. मैकफैडजेन का कहना है, "हम चाहेंगे कि खिलाड़ी भी इन हालातों और कारणों की कड़ी को जोड़ने पर अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि वे प्रभावशाली होते हैं और उनकी इन चिंताओं पर राय रखने की जिम्मेदारी है।

आखिर हमारी पृथ्वी भी इन नायकों से कुछ उत्तरदायित्व पूरे करने की उम्मीद तो रख ही सकती है। आस्ट्रेलिया हो या अमेजन या कहीं और आपदा के वक्त इनसे सारी दुनिया प्रभावित होती है। और ऐसे में इसके भरपाई की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों या समर्पित पर्यावरणविदों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिये।

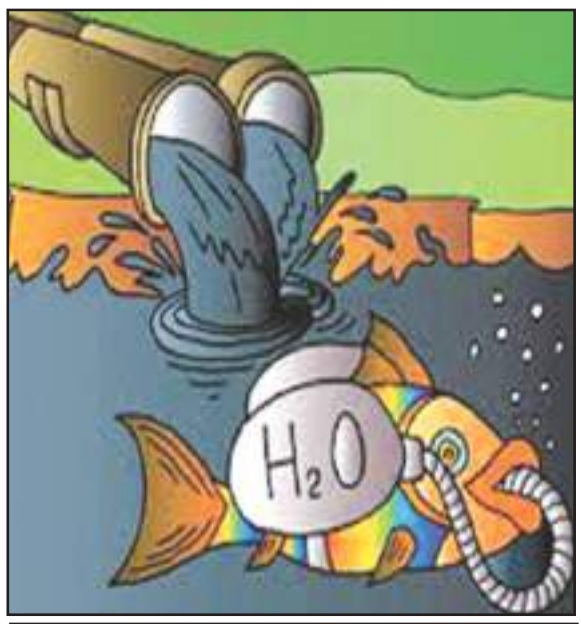

गेहूं की पैदावार कम कर देते हैं खरपतवार

गेहूं हमारे देश की मुख्य फसल है, परंतु झारखंड में गेहूं की उत्पादकता पड़ोसी राज्यों व राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इसे बढ़ाने की असीम संभावनाएं हैं। गेहूं फसल को हानि पहुंचाने वाले विभिन्न कारकों में सबसे अधिक हानि खरपतवार पहुंचाते हैं। ये अवांछनीय पौधे गेहूं में उगकर पोषक तत्वों, नमी, वायु, प्रकाश व स्थान आदि के लिए स्पर्धा कर फसल को कमजोर बना देते हैं।

हानिकारक कीटों व बीमारियों का आश्रय स्थल बनकर फसल की उपज व गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। गेहूं की फसल में खरपतवारों से होने वाले नुकसान को 25-75 प्रतिशत तक आंका गया है। किसान प्रायः अपनी फसल में निकलने वाले खरपतवारों को जानवरों के चारे के लिए उपयोग करने के लिए समय पर इनका नियंत्रण नहीं करते व इससे उनकी उपज में भारी कमी आ जाती है।

खरपतवार नियंत्रण के लिए गेहूं की प्रारंभिक अवस्था, जोकि 30-45 दिन आंकी गई है अति महत्वपूर्ण है। इसमें इनका निदान किसी भी विधि से अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा फसल के उत्पादन में कमी आती है। गेहूं में खरपतवारों की रोकथाम के लिए किसान कई तरीके अपना सकते हैं। इनमें दवाइयों का छिड़काव से लेकर निराई-गुड़ाई से भी खरपतवार पर अंकुश लगाया जा सकता है।

यह सावधानियां बरतें किसान

- खरपतवारनाशी का प्रयोग करते समय खेतों में नमी का होना आवश्यक है।
- खरपतवार के प्रकार और संख्या को ध्यान में रखकर खरपतवारनाशी का चुनाव करें।
- छिड़ककाव करते समय खरपतवार व फसल की अवस्था का ध्यान रखें। छिड़काव फ्लैट फैन नोजिल लगे पंप से ही करें।
- खरपतवारनाशी का सही मात्रा, सही समय एवं उपयुक्त तकनीक से छिड़काव करें।
- गेहूं में खरपतवार निवारण के लिए खरपतवार नाशी को अदल-बदल कर उपयोग में लाएं।

शोध के बाद नई सर्पविषरोधी दवा जल्द हो सकती है तैयार

देवांग्शु दता

बेंगलूरु के साइजीनोम रिसर्च फाउंडेशन के सोमशेखर शेषगिरि की अगुआई में 42 वैज्ञानिकों के दल ने नाग की भारतीय प्रजाति नाजा नाजा के जीनोम का क्रम तैयार किया है। इससे जल्दी ही सर्पविषरोधी दवा के उत्पादन की तकनीक में सुधार आ सकता है। साथ ही इससे ऐसी व्यापक सर्पविषरोधी दवा तैयार की जा सकती है जो विभिन्न तरह के सांपों के विष के खिलाफ कारगर साबित होगी।

सांप के कांटने से भारत में हर साल 46,000 लोगों की मौत हो जाती है। भारत के अलावा पूरी दुनिया में सर्पदंश से सालाना करीब 55,000 लोग मारे जाते हैं। इसी तरह 500,000 लोग सर्पदंश के कारण भारी दर्द, अपंगता और लकवे का शिकार हो जाते हैं और कई लोगों के अंग काटने पड़ते हैं। भारत में सर्पदंश के अधिकांश मामले सांपों की चार प्रजातियों करैत, नाग, सॉ-स्केल्ड वाइपर और रसेल वाइपर से जुड़े होते हैं। हालांकि भारत में विषैले सांपों की 60 से अधिक प्रजातियां हैं।

सांप का जहर विभिन्न तरह के प्रोटीन और पेप्टाइड का मिश्रण होता है जिसका स्राव विषग्रंथि से होता है। सांप के जहर को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों न्यूरोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक या हीमोटॉक्सिक में बांटा जा सकता है। अलग-अलग प्रजाति के सांपों में अलग तरह का विष पाया जाता है। न्यूरो विष से लकवा हो सकता है, साइटो विष रक्त कोशिकाओं को तोड़ता है जबकि कार्डियो विष से हृदय काम करना बंद कर सकता है। हीमो विष रक्त में ऑक्सीजन के साथ मिलता है जिससे दम घुट सकता है। सर्पविषरोधी दवा का निर्माण मुश्किल, श्रमसाध्य और महंगी प्रक्रिया है और प्रकृति में इसकी मात्रा बहुत कम है।

पहले तो सांप को विष संग्रह जार के ऊपर लटकते मांस को काटने के लिए उकसाया जाता है। इस तरह विष एकत्र किया जाता है। इसके बाद इसका बहुत थोड़ा गैर-विषैला हिस्सा घोड़े को इंजेक्ट किया जाता है। घोड़ा एंटीबॉडी बनाकर इसके प्रभाव से लड़ता है। इस-के बाद घोड़े के रक्त के प्रसंस्करण से सर्पविषरोधी दवा बनाई जाती है। लेकिन इसमें घोड़े की बीमारियों के लिए विशिष्टद्द दूसरी एंटीबॉडी भी होती हैं। ये न केवल मनुष्य के लिए अप्रासंगिक है बल्कि इससे भयानक एलर्जी भी हो सकती है। कई सर्पविषरोधी दवाओं को मिलाकर एक व्यापक दवा बनाई जा सकती है लेकिन यह सफल या नाकाम प्रयोग हो सकता है, जहां सर्पविषरोधी दवा कुछ खास सांपों के अलावा दूसरे सांपों के काटने पर कारगर नहीं होगी। इसे सबसे पहले 1890 के दशक में इस्तेमाल किया गया था और आज के आधुनिक तरीके भी कमोबेश उसी तरह के हैं। एक बड़ी बाधा यह है कि शोध के लिए पर्याप्त मात्रा में सर्पविष नहीं है। 'नेचर जेनेटिक्स' में प्रकाशित एक नए शोधपत्र में दावा किया गया है कि नाजा नाजा के 38 गुणसूत्रों में से 95 फीसदी जीनोम डिकोड कर लिया गया है। इसमें विषग्रंथि के जीनोम पर खास जोर दिया गया है। शोध दल ने 14 विभिन्न प्रजातियों के नागों के ऊतकों के जीन एक्सप्रेशन डेटा का इस्तेमाल किया।

इसमें कहा गया है कि 12,346 जीन विषग्रंथि से ताल्लुक रखते हैं और इनमें 139 का ताल्लुक 33 विषैली प्रकृति के जीन परिवार से हैं। 139 विषैली जीन में से 19 जीन खासतौर पर विषग्रंथि को दर्शाती हैं और संभवतः ये न्यूनतम मुख्य विष प्रभावकारी प्रोटीन को कूटबद्ध करते हैं। शोधकर्ताओं को यह पता लगाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी कि कौन सी जीन केवल विषग्रंथि से जुड़ी है।

विष के निर्माण की गुत्थी सुलझाने और दवा बनाने के लिए 33 विषैले परिवारों से ताल्लुक रखने वाली 139 जीनों का समूह और नाग से जुड़े 19 जीन बेहद अहम हैं। यदि इनका संश्लेषण होता है तो सबसे पहले इनका इस्तेमाल बड़ी संख्या में सिंथेटिक विष बनाने में हो सकता है। फिर इससे सिंथेटिक सर्पविषरोधी दवा बनाया जा सकता है। इस तरह का सिंथेटिक सर्पविषरोधी दवा में एलर्जी पैदा करने वाली घोड़े की एंटीबॉडीज नहीं होगी। इसमें पुनःसंयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी मददगार साबित हो सकती है जिसमें विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। हर विष के आनुवंशिक क्रम को बढ़ाने के लिए खमीर या ई-कोलाई में डाला जाएगा और इससे बड़ी मात्रा में अलग-अलग विष का उत्पादन होगा। फिर हर विष को मानव ऐंटीबॉडी के साथ मिलाया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सा विष कारगर है। फिर विभिन्न प्रकार के विष के मिश्रणों के साथ ऐसा किया जा सकता है।

यह प्रक्रिया बेहद जटिल और श्रमसाध्य है लेकिन इससे बेहतर सर्पविषरोधी दवा बन सकती है। एक बार दूसरे सांपों का जीनोम मैप होने के बाद व्यापक सर्पदंशरोधी दवा बन सकती है। इससे आधुनिक प्रयोगशाला प्रक्रियाएं भी विकसित हो सकती हैं जिससे घोड़े को शामिल किए बिना उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। यह प्रक्रिया महंगी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों की संख्या आधा करने का लक्ष्य रखा है। इसलिए नई सर्पदंशरोधी दवा बनाने के लिए पैसों की समस्या नहीं होगी।

शोध के अनुसार, जीनोम को सर्प जीनोम के लिए संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यह आगे आने वाले अध्ययनों में मददगार साबित हो सकता है और इससे विष आधारित औषधि की खोज का रास्ता साफ होगा। विष से जुड़ी विशिष्टद्द जीनों की पहचान के लिए जिन विधियों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें दूसरे सांपों के जीनोम को डिकोड करने में उपयोग किया जा सकता है। सांप के विष के प्रभावों को अभी तक अच्छी तरह नहीं समझा गया है लेकिन विष के सक्रिय तत्त्वों से कई तरह की दवाएं बनाई जाती हैं। इनसे रक्तचाप काबू में रखने और थक्के को तोडने में मदद मिलती है। इस तरह यह शोधपत्र सर्पदंश के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी है। डब्ल्यूएचओ ने सर्पदंश को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी में श्रेणीबद्ध किया है। ●

आम बजट : कृषि क्षेत्र के लिए सरकार को क्या करना चाहिए?

ए के भट्टाचार्य

क्या केंद्र सरकार कृषि पर पर्याप्त खर्च कर रही है? आम बजट से पहले यह सवाल फिर सुर्खियों में है। खासकर, इसलिए क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा संसाधनों के आवंटन की मांग की जा रही है। इसके पीछे यह सोच है कि कृषि पर व्यय बढने से भारतीय किसानों के हाथों में खर्च करने योग्य आय बढ़ेगी और मांग बढने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौटेगी। ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए?पिछले कई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्रियों ने भाषणों में किसानों के कल्याण के वास्ते बड़ी-बड़ी बातें कीं लेकिन कृषि क्षेत्र के लिए बजट का पर्याप्त आवंटन नहीं किया। उदाहरण के लिए 2017-18 का ही बजट लीजिए जिसके लिए अंकेक्षित आंकड़े उपलब्ध हैं। इसमें करीब एक दर्जन पैराग्राफ किसानों को समर्पित थे। लेकिन पिछले साल जुलाई में जारी 'बजटः एक नजर' दस्तावेज के मुताबिक कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर कुल 52,628 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने का अनुमान है जो 2017-18 में सरकार के कुल व्यय का महज 2.45 फीसदी है। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की घोषणा के बाद इसमें थोड़ा अंतर आया है। 2019-20 के अंतरिम बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी और इसके तहत दो हेक्टेयर से कम जोत वाले सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये नकद देने का वादा किया गया था। इस योजना को पिछली तारीख से 1 दिसंबर, 2018 से लागू किया गया और देश में करीब 86 फीसदी कृषि योग्य भूमि इसके दायरे में हैं। कृषि और संबंधित गतिविधियों पर सरकार का खर्च 2018-19 में बढ़कर 86,602 करोड़ रुपये पहुंच गया जो उस साल सरकार के कुल खर्च का 3.5 फीसदी था। अगर इसमें से पीएम-किसान की राशि को हटा दें तो कृषि क्षेत्र पर सरकारी व्यय केवल 66,602 करोड़ रुपये यानी सरकार के कुल खर्च का महज 2.7 फीसदी था। 2019-20 में पूरे साल के लिए पीएम-किसान योजना की राशि दी गई जिससे कृषि और संबंधित गतिविधियों पर सरकार का खर्च बढ़कर 1.51 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया जो कुल सरकारी खर्च का करीब 5.4 फीसदी है। उल्लेखनीय है कि इसमें से करीब आधी राशि (75,000 करोड़ रुपये) पीएम-किसान के हिस्से की थी। सरकार ने अब इस योजना का दायरा बढ़ाकर सभी किसानों को इसमें शामिल कर लिया है जिससे इसका वार्षिक व्यय बढ़कर 89,000 करोड़ रुपये पहुंचने की संभावना है। कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों पर सरकारी खर्च में पीएम-किसान की सबसे अधिक हिस्सेदारी है। संभवतः हाल के वर्षों में यह किसानों के लिए सबसे बड़ी बजट घोषणा थी। किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष नकदी अंतरण कृषि पर खर्च का सबसे जरिया बन गया है। शायद यही आगे का रास्ता है। किसानों को प्रत्यक्ष नकदी अंतरण के तहत ज्यादा राशि दीजिए और उन्हें ही यह करने दीजिए कि इसे कहां और कैसे खर्च करना है। यह ग्रामीण भारत के लिए आंशिक आय समर्थन योजना की तरह होगा। मांग पर इसका वृद्धिशील प्रभाव उल्लेखनीय होगा, किसानों की आय पर इस-का उल्लेखनीय प्रभाव होगा और इस योजना के कारण अतिरिक्त खर्च का बोझ अपेक्षाकृत मध्यम होगा। अगर हर किसान परिवार को सालाना नकदी अंतरण की राशि दोगुना भी की जाती है तो भी अतिरिक्त खर्च केवल 90,000 करोड़ रुपये होगा। संक्षेप में कहें तो 2020-21 के आम बजट में कांग्रेस की न्याय (न्यूनतम आय योजना) की अपने ढंग से पैकेजिंग की जा सकती है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दम मिलेगा। कृषि पर सरकार का खर्च केवल पीएम-किसान या फसल बीमा, कृषि ऋण पर ब्याज सब्सिडी या किसानों के लिए पेंशन तक ही सीमित नहीं है। सरकार उ-र्वरक और खाद्य सब्सिडी पर भी अच्छी खासी राशि खर्च करती है जिससे अप्रत्यक्ष तौर पर किसानों को फायदा होता है।

उदाहरण के लिए 2019-20 में सरकार के उर्वरक सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपये और खाद्य सब्सिडी पर 1.84 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है। इस तरह 2019-20 में किसानों की कल्याणकारी योजनाओं पर सरकारी खर्च करीब 4.15 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है जबकि 2018-19 में यह राशि 3.28 लाख करोड़ रुपये और 2017-18 में 2.19 लाख करोड़ रुपये थी। इस सब्सिडी को ज्यादा कारगर और लाभार्थियों के लिए लक्षित बनाने के वास्ते बजट में क्या किया जा सकता है?

अनाज की खरीद में भी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के इस्तेमाल के लिए बजट में एक योजना पर विचार होना चाहिए और इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। पहले ही सरकार यह सुनिश्चित कर चुकी है कि उर्वरक पर सब्सिडी किसानों को वास्तविक बिक्री के आधार पर ही जारी की जाए। अब ऐसी व्यवस्था का समय आ गया है कि गेहूं और धान का खरीद मूल्य सीधे किसानों के बैंक खाते में जाए। अगर जरूरी हुआ तो इसके लिए आधार आधारित पहचान प्रणाली का इस्तेमाल किया जा सकता है।

ओडिशा और पंजाब की सरकारें अपने राज्यों में इसी तरह की योजना लाने की कोशिश कर रही हैं। 2020-21 के आम बजट में पूरे देश में इस तरह की योजना लाने पर विचार किया जा सकता है। इससे सब्सिडी योजनाओं की खामियों को दूर कर इनकी लागत में कटौती हो सकती है। साथ ही देश में मौजूदा अनाज खरीद प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है।अंत में बजट में कृषि में निवेश बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है। नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर हाल में जारी रिपोर्ट के मुताबिक बजट में 22,000 ग्रामीण हाट को ग्रामीण कृषि बाजार में अपग्रेड करने के लिए राशि आवंटित की जानी चाहिए। बजट में आने वाले वर्षों में कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में निवेश की योजना का खाका तो पेश किया ही जा सकता है।

मलेशिया-इंडोनेशिया के बीच छिड़ेगा कीमत युद्ध !

रिफाइंड पाम तेल आयात पर भारत द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने से मलेशिया की बाजार हिस्सेदारी को नुकसान होगा। इससे उसके प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ता देश इंडोनेशिया के साथ कीमत युद्ध शुरू होने की आशंका है। मलेशिया के एक औद्योगिक संगठन ने यह जानकारी दी। पाम ऑयल रिफाइनर्स एसोसिएशन ऑफ मलेशिया (पीओआरएएम) ने कहा कि भारत द्वारा प्रतिबंध लगाने का मतलब यह है कि मलेशिया को अब भारत को कच्चा पाम तेल बेचने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी जिसमें इंडोनेशिया कीमत के लिहाज से ज्यादा किफायती रहा है। पीओआरएएम के चेयरमैन जमील हारून ने कहा, 'भारत सरकार के इस निर्णय ने इंडोनेशिया और मलेशिया को आमने सामने ला खड़ा किया है। अब इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच कीमत युद्घ की नौबत आएगी और हमें नुकसान होगा।' उन्होंने कहा, 'हम अब भी कच्चा पाम तेल बेच सकते हैं, लेकिन अब हमें इंडोनेशिया के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी।' पिछले वर्ष इंडोनेशिया को पीछे छोड़ मलेशिया भारत का सबसे बड़ा पाम तेल आपूर्तिकर्ता बन गया गया था। कुआलालंपुर स्थित एक व्यापारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि मौजूदा अनुबंध खत्म होने से मलेशिया के निर्यात में जनवरी के अंत से कमी आने लगेगी। मलेशिया के पाम तेल संघ के मुख्य कार्याधिकारी नजीब वहाब ने कहा कि रिफाइंड तेल निर्यात पर नियंत्रण से भारतीय रिफाइनरों को लाभ होगा

मच्छर ही दिलाएंगे डेंगू से छुटकारा

वैज्ञानिकों ने मच्छरों में कृत्रिम रूप से बदलाव करने में सफलता हासिल की है, जिस-की मदद से यह मच्छर ही डेंगू वायरस को फैलने से रोक देंगे। डेंगू वायरस से निपटने के लिए बायोलॉजिस्ट्स ने इन एडीज एजिप्टी मच्छरों से निपटने के लिए एक प्रतिरक्षी दवा बनाने में सफलता हासिल की है, जोकि डेंगू फैलाने वाले इन मच्छरों का दमन करने में सक्षम है। यह दवा अब तक ज्ञात चारों प्रकार के डेंगू वायरस से निपटने में कारगर है, जोकि इससे पहले तैयार प्रतिरक्षी दवावों को और बेहतर बनाती है। यह अध्ययन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के जीव विज्ञानियों द्वारा किया गया है जोकि जर्नल प्लॉस पैथोजन्स में प्रकाशित हुआ है।

खेतों में जाकर बचाव के तरीके तलाशेंगे वैज्ञानिक

उत्तर प्रदेश में फसलों पर संकट
1.50 करोड़ का बजट स्वीकृत

एजेंसियां : लगातार बिगड़ते मौसम और जलवायु परिवर्तन से फसलों पर पड़ रहे प्रभाव, उत्पादन में आ रही गिरावट और मृदा में आर्गेनिक कार्बन की कमी को दूर करने के लिए कृषि वैज्ञानिक अब खेतों पर जाकर शोध करेंगे।

इसके लिए मेरठ के हस्तिनापुर में 300 हेक्टेयर भूमि पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुनी गई है।

आखिर कैसे वैज्ञानिक खोजेंगे फसलों को संकट से बचाने के तरीके यह अभियान उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में चलेगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हस्तिनापुर क्षेत्र में 300 हेक्टेयर भूमि पर शोध किया जाएगा।इसके लिए यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (उपकार) ने भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान को डेढ़ करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। जिसके बाद दूसरे जिलों में काम शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट में आईआईएफएसआर के वैज्ञानिक स्थानीय किसानों के साथ मिलकर काम करेंगे।

गंगा के आसपास होगा शोध

भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. आजाद सिंह पंवार के अनुसार गंगा के आसपास यह प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। गंगा के सहयोग से वहां पर ग्रीन गैसों को कम करने का काम किया जाएगा। जिससे रिसर्च में काफी मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट पर काम करने से किसान अपने यहां भी इन तकनीक से खेती कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए कमेटी गठित की गई है, जिसमें वैज्ञानिक डॉ. एमपी सिंह, डॉ. निशा, डॉ. एके पुरुस्ति, डॉ. पीसी जाट, डॉ. पूनम कश्यप आदि कार्य करेंगे।आर्गेनिक फार्मिंग पर काम होगा।कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। संरक्षित खेती को तकनीक से किया जाएगा। मृदा एवं जल संरक्षण पर काम होगा। पशु नस्ल में सुधार किया जाएगा। मछली पालन किया जाएगा। मशरूम, शहद उत्पादन भी होगा। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम किया जाएगा।

इन जिलों में चलेगा प्रोजेक्ट

वेस्टर्न जोन : मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर
मिड वेस्टर्न जोन : अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर
साउथवेस्टर्न जोन : मथुरा, आगरा, एटा
तराई जोनः लखीमपुर खीरी, बहराइच, सहारनपुर
सेंट्रल जोन : फतेहपुर, कानपुर देहात, हरदोई, सीतापुर
ईस्टर्न जोनः अयोध्या, चंदौली, मऊ
नॉर्थ ईस्ट जोन : सिद्धार्थनगर, देवरिया, गोरखपुर
विंध्याचल जोन : प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर
बुंदेलखंड जोन : झांसीकिसानों के लिए बहुत उपयोगी

यह बड़ी परियोजना है। यूपी के 26 जिलों में चलाई जाएगी। हस्तिनापुर क्षेत्र में 300 हेक्टेयर भूमि पर काम होगा। किसानों के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत ही उपयोगी होगा।

सीसीएल में पूर्ण नियंत्रित ब्लास्टिंग विधि पर प्रस्तुति

रांची :हैदरबाद स्थित कंपनी मेसर्स सिबी माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने सीसीएल के कॉन्फ्रेंस हॉल(न्यू. बिल्डिंग) प्रबंधन के समक्ष पूर्ण नियंत्रित ब्लास्टिंग विधियों पर प्रस्तुति दी। मेसर्स सिबी माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री सिबी लूकोस के अनुसार, पूर्ण नियंत्रित ब्लास्टिंग में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुवे 10 मीटर के करीब ब्लास्टिंग किया जाता है और इस प्रकिर्या में न्यूनतम कंपन होता है। सीसीएल के निदेशक तकनीकी (परियोजना और योजना) भोला सिंह, महाप्रबंधक (संचालन) आईसी मेहता, महाप्रबंधक/सीएमडी के तकनिकी सचिव एम.वी. राजिमवाले, निदेशक (तकनिकी संचालन) के सचिव के एस गयवाल, महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं बचाव) एस वी मराठे, सभी क्षेत्रों के सुरक्षा अधिकारीगण, सिबी माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के जीएम के.के सिंह एंड ओरिका के प्रतिनिधिगण प्रस्तुति के दौरान उपस्थित थे। भी उपस्तिथ थे।

खेल और खिलाड़ियों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनेंगी

रांची: झारखंड राज्य के दल ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को बताया कि लखनऊ में द्वितीय स्थान(मार्च पास्ट झांकी) एवं पेंटिंग में तृतीय स्थान मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम युवाओं, कला संस्कृति और खेल कूद को बढ़ावा देंगे। खेल और खिलाड़ियों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनेंगी।

मुख्यमंत्री ने गहरी संवेदना व्यक्त की

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने ट्विटर के माध्यम आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद इलाज के अभाव में 12 वर्षीय किशोर जिसके हृदय में छेद था की मृत्यु पर परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना प्रकट करते हुए पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को उक्त परिवार की सहायता करने का निदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि झारखंड के प्रत्येक घर को चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो।

बीएयू में छोटे किसानों के लिए कुशल और प्रभावी विपणन प्रणाली का विकास पर कार्यशाला आयोजित

किसान हित पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत : मुख्य महाप्रबंधक

रांची : देश के बहुतायत किसान औसतन एक एकड़ भूमि के जोतदार हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों के किसान औसतन 11 हेक्टेयर भूमि के जोतदार हैं। देश में इन छोटे जोतदार की स्थिति दयनीय है। देश के सभी कृषि से जुड़े हितकारकों को इनके हितों और अपेक्षा पर गंभीर सोच एवं सार्थक प्रयास की जरूरत है। इन किसानों को कृषि उत्पाद का 35 प्रतिशत ही मूल्य मिल पाता है, जबकि 65 प्रतिशत लाभ बिचौलियों को मिलता है। इस व्यवस्था को पारदर्शी, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली युक्त कुशल और प्रभावी विपणन प्रणाली के माध्यम से दूर किया जा सकता है। उक्त बातें मुख्य अतिथि नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक एके पाधि ने कही। वे 11 जनवरी को बीएयू में 'छोटे किसानों के लिए कुशल और प्रभावी विपणन प्रणाली का विकास' विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के उदघाटन अवसर पर बोल रहे थे।

एकेपाधि ने कहा कि कृषि उत्पादों का सीधा लाभ किसानों और उपभोक्ता को मिलना चाहिए। किसानों की स्थिति में सुधार के लिए स्थानीय स्तर पर कृषि विपणन प्रणाली को सशक्त किये जाने की आवश्यकता है। इस ओर सुधार के प्रयास चल रहे है, जो जल्द ही देखने को मिलेंगे। मेधा डेयरी के महाप्रबंधक एसके सिंह ने कहा कि देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता समिति के माध्यम से छोटे किसानों को काफी लाभ मिला है। इन छोटे किसानों के बल पर गुजरात की अमूल, बिहार की सुधा और झारखंड की मेधा डेयरी ब्रांड की विशेष पहचान है। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष पहले 9 हजार लीटर दुग्ध उत्पादन से शुरू किया गया मेधा डेयरी आज 1.25 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन कर रहा है। उन्होंने छोटे किसानों के सामूहिक खेती करने एवं कृषि उत्पाद का सही मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सशक्त विपणन प्रणाली को प्रभावी विकल्प बताया। मौके पर जेजीबी ग्रुप, कोलकाता के महाप्रबंधक और उद्यमी अंकुश साहा ने अपने 5 वर्षो के अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि गुणवत्ता वाली कृषि उत्पादों के निर्यात से किसानों की आय दोगुनी हो सकती है। उन्होंने 3 पार्टनर के साथ 5 वर्ष पहले ताजी सब्जी एवं फल निर्यात का उद्यम शुरू किया। बेहतर उत्पाद और मार्केटिंग के बल पर आज उनके साथ 50 कर्मचारी और 1 हजार किसानों को रोजगार मिल रहा है।

कास्ट परियोजना सह अन्वेषक डॉ बीके अग्रवाल ने कृषि छात्रों एवं किसानों को कृषि विपणन प्रणाली के प्रति प्रेरित करने के लिए कार्यशाला आयोजन की बात कही। इस अवसर पर परियोजना अन्वेषक डॉ एमएस मल्लिक ने कास्ट परियोजना के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में बताया। कार्यक्रम का समन्वय डॉ बीके झा, संचालन श्रीमती नेहा पांडे और धन्यवाद डॉ सुशील प्रसाद ने किया। मौके पर डॉ डीएन सिंह, डॉ आरपी सिंह, डॉ जे उरांव, डॉ जेडए हैदर, डॉ ए वदूद, डॉ डीके शाही, डॉ राकेश कुमार सहित बीएयू वैज्ञानिक, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि, किसान और छात्र भी मौजूद थे।

सीसीएल के लाल का जेईई मेन्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन

संवाददाता

रांची : सीसीएल के लाल सिद्धांत शेखर को जेईई मेन्स में 99.25 पर्सेन्टाईलसेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल.) की महत्वाकांक्षी योजना 'सीसीएल के लाल' के सिद्धांत शेखर को जेईई मेन्स में 99.25 पर्सेन्टाईल साथ ही बैच के 16 में से 11 बच्चों ने जेईई मेन्स में 90 पर्सेन्टाईल से ज्यादा प्राप्त कर एक बार फिर अपना परचम लहराया है।

सीसीएल के लाल की छात्रों की सूची

सिद्धांत शेखर, विक्की कुमार नायक, अभिषेक कुमार सिन्हा, किशन कुमार, बिटू कुमार, विशाल कुमार, शुभम कुमार, तबिस हसन, अमन कुमार, ध्रुव कुमार साहू, अमन गुप्ता, बिटू यादव, भागिरथ महतो, रवि कुमार, आदर्श कुमार एवं प्रियाशु कुमार दूबे।सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह अपने दैनिक कार्य के उपरांत सीसीएल गांधीनगर कॉलोनी स्थित सीसीएल के लाल एवं सीसीएल के लाडली के कोचिंग सेन्टर में बच्चों से मिलें। बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सीएमडी सीसीएल न गोपाल सिंह ने बधाई दी और जेईई एडवांस के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम बच्चों का भविष्य संवारते है इसलिए कोयला निकालते हैं। सीएमडी सिंह ने बच्चों को अगले कुछ महिनों में अपनी पूरी क्षमता के साथ मेहनत एवं लगन से एडवांस की तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित किया। सीसीएल के लाल भी बैचों के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश के प्रख्यात इंजीनियरिंग कॉलजों में प्रवेश प्राप्त किया है जिसमें लगभग 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे आईआईटी एवं एनआईटी में रहे हैं। सीसीएल के लाल-लाडली बैच 2020-22 के लिए समस्त झारखंड राज्य में 10वीं में पढ़ रहे जरूरतमंद बच्चों के लिए आईआईटी जेईई व अन्य इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के तैयारी के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है । इन बच्चों को सीसीएल में कार्यरत आईआईटीयन अधिकारी निःशुल्क कोचिंग देंगे। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत रांची में निःशुल्क रहने, खाने, स्कूली शिक्षा, शैक्षणिक सुविधाएं भी दी जायेंगी। इस वर्ष आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः

ऑनलाईन कर दी गयी है जिसे आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। आवेददन करने के लिए सीसीएल के वेबसाईट www.centralcoalfields.in पर जायें या www.cclkelalandlaadli.in से भी किया जा सकता है। आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। ज्ञातव्य हो कि इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरूआत वर्ष 2012 में सीएमडी गोपाल सिंह के मार्गनिर्देशन में किया गया था जिसमें जरूरतमंद बबच्चों को निःशुल्क आईआईटी करायी जाती है। सीसीएल के अधिकारीगण जितेन्द्र कुमार, अखिलेश कुमार, नमन श्रीवास्तव, अनुभव खरे, ओम प्रकाश एवं देव प्रकाश सिंह जो स्वंय आईआईटी के छात्र रहे हैं वे स्वतः सीसीएल के लाल एवं सीसीएल की लाडली का प्रशिक्षण शिक्षक के रूप में योगदान दे रहें हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे प्रतिभावान छात्र जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं और उन्हें सीसीएल द्वारा डीएवी स्कूल गांधीनगर, रांची में दाखिला कर निःशुल्क शिक्षण, आवास एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जा रहा है। सीसीएल के लाल एवं सीसीएल की लाडली के बच्चों का चयन 10वीं कक्षा के बाद किया जाता है। सभी छात्रों को 11वीं और 12वीं कक्षा के साथ-साथ आईआईटी-जेईई का भी निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है।

कोल इंडिया को और मजबूत करेगी भारत सरकारः प्रल्हाद जोशी

कोल इंडिया को और मजबूत करेगी भारत सरकारः श्री प्रल्हाद जोशी

कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि भारत सरकार अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को और मजबूत बनाने एवं उसका विस्तार करने के लिए निरंतर कटिबद्ध है। इन्हीं प्रयासों के तहत कोल इंडिया का कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल ही में कंपनी को 16 नए कोयला ब्लॉक आवंटित किए हैं। इस आवंटन के साथ कोल इंडिया के पास अब 463 कोयला ब्लॉक हो गए हैं और कंपनी का खनन योग्य कोयला रिज़र्व बढ़कर 52,000 मिलियन टन (एमटी) हो गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कोल इंडिया ने 606 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया था, जिसमें 488 मिलियन टन कोयले की सप्लाई तापीय बिजली उत्पादन के लिए की गई थी। देश की तापीय बिजली की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर, कोल इंडिया के पास उपलब्ध खनन योग्य कोयला भंडार से देश की आगामी 100 वर्षों से अधिक तक की तापीय बिजली बनाई जा सकती है। पत्रकारों से बात करते हुए श्री जोशी ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर कोल इंडिया को और भी कोयला ब्लॉक आवंटित किए जाने सहित हरसंभव सहायता की जाएगी। कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग शुरू होने से कोल इंडिया के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि भविष्य में भी देश की बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी कोयला आपूर्ति करने का मुख्य स्रोत कोल इंडिया ही बनी रहेगी। कोल इंडिया को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1000 मिलियन टन यानी 01 बिलियन टन कोयला उत्पादन करने का लक्ष्य दिया गया है।

श्री जोशी ने कहा कि देश को विकास के पथ पर और भी तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए आगामी 30-40 वर्षों में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयले की मांग भी बढ़ेगी। कमर्शियल माइनिंग का उद्देश्य इसी बढ़ी हुई मांग को पूरा करना और कोयला आयात पर देश की निर्भरता को कम करना है।

गौरतलब है कि कोल इंडिया विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। कोल इंडिया अकेले भारत का लगभग 82% कोयला उत्पादन करती है। कोयला खनन की लागत काम करने, उत्पादकता बढ़ाने एवं खनिकों की कार्य सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए कोल इंडिया तेजी से अपनी खदानों में नवीनतम तकनीक से युक्त मशीनों का प्रयोग बढ़ा रही है।

संजय कुमार वर्मा बनें मेकॉन लिमिटेड के नए निदेशक (वाणिज्य)

रांची :भारत सरकार के संस्थान मेकॉन लिमिटेड़ में श्री संजय वर्मा ने कल निदेशक (वाणिज्य) का पद ग्रहण किया श्री वर्मा ने वर्ष 1988 में बीआईटी सिंदरी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद मेकॉन में ग्रेजुएट इंजीनियर के तौर पर जॉइन किया । श्री वर्मा, के पास लौह और इस्पात प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, विपणन और अनुबंधों में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है और उन्होंने डीईसी व पीएमसी सेवाओं के लिए विविध परियोजनाओं में तकनीकी और वाणिज्यिक क्षमताओं के साथ कार्य का निष्पादन किया । श्री वर्मा ब्लास्ट फर्नेस विशेषज्ञ के रूप में जाने पहचाने जाते हैं, जिन्होंने पूरे देश में कई प्रतिष्ठित बीएफ परियोजनाओं को पूरा किया है।श्री वर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुभव के साथ अग्रणी व्यापारिक संगठनों में सफलतापूर्वक दो दशक तक योगदान दिया है । वह 2014 से तीन एसबीयू (धातु, ऊर्जा और संरचना) के व्यवसाय विकास, विपणन और वाणिज्यिक कार्यों का नेतृत्व कर रहे हैं ।

युवा राजपुताना एकता मंच ने मनाया महाराणा प्रताप का पुण्य तिथि

रांची : युवा राजपुताना एकता मंच एवं छात्र क्लब ग्रुप की ओर से हरमू हाउसिंह कॉलोनी सीत वीर अभिमन्यु चौक में महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि मनाया गया। इस अवसर पर दोनों संस्थाओं के प्रमुख पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार , अभिषेक कुमार, शिव किशोर शर्मा, राघवेंद्र सिंह, कमलेश यादव श्रीराम सिंह, मुकेश कुमार सिंह, समीर सिंह मौजूद रहे। अभिषेक कुमार सिंह ने महाराणा प्रताप की जीवनी पर प्रकाश डाला और बताया कि महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया था और हल्दी घाटी युद्ध में पराजय के बाद फिर से सेना एकत्र कर वापस अपने क्षेत्र को प्राप्त किया। संस्था के लोगों ने वीर अभिमन्यु चौक के निकट स्वच्छता अभियान भी चलाया।

हमारी सरकार गरीब गुरबों के लिये पूरी तरह से समर्पित है: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार गरीब गुरबा के हित के लिए पूरी तरह समर्पित है और उनके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा विकसित और समृद्ध झारखंड के निर्माण में मिशनरीज समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मानव सेवा सहित अनेक क्षेत्र में इस समाज ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनके द्वारा समाज में किए गए नेक कार्यों को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे अपने जीवन काल में इस समाज के साथ कई मौकों पर रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य में चर्च समूह जो भी कार्य करते हैं पूरी दृढ़ता और संकल्प के साथ उसे पूरा करते हैं'। अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं

अखिल भारतीय वैश्व महासम्मेलन की बैठक

रांची :आज दिनांक 15.01.2020 को अखिल भारतीय वैश्व महासम्मेलन, झारखण्ड प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों की महत्वपुर्ण बैठक रातु रोड़ अमरूद बगान स्थित मंजुला फार्म हाउस में सम्पन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ बच्चो के बीच चुड़ा, दही, तिलकुट आदि वितरण कर एवं मंजुला फार्म हाउस में पौधारोपण कर हुई। बैठक में राष्ट्रीय मंत्री डॉ0 बिजय प्रकाश ने बताया संगठन को मजबुत करने के लिए विस्तार करना अति आवश्यक है साथ ही राज्यहित में विकास के मॉडल पर झारखण्ड सरकार के नये मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय लेने के लिए चर्चा हुई यह भी निर्णय लिया गया झारखण्ड के सभी वैश्व विधायकों को सम्मान समारोह किया जायेगा जिसका उद्धघाटन माननीय मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से कराने का सकल्प लिया गया। कार्यक्रम की समाप्ति वरीय ललित चैधरी एवं संजय चौधरी द्वारा छात्र क्लब ग्रुप को काफी संख्या में गर्म वस्त्र भेटकर किया गया। छात्र क्लब ग्रुप द्वारा यह गर्म वस्त्र ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद लोगो के बीच वितरण कर किया जायेगा। बैठक में प्रधान महासचिव ललित कु0 चैधरी,प्रदेश महासचिव संजय चैधरी, प्रदेश मिडिया प्रभारी शिव किशोर शर्मा एवं ब्रज मोहन गुप्ता, रंजीत कु0 सोनी,सुनील प्रसाद, श्याम स्वामी गुप्ता आदि उपस्थित थे।

सीएमपीडीआई अंतर क्षेत्रीय संस्थान सांस्कृतिक प्रतियोगिता संपन्न

रांची : सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय संस्थान-3, रांची के तत्वावधान में संस्थान के ''मयूरी हॉल'' में 16 जनवरी से 18 जनवरी, 2020 तक आयोजित तीन दिवसीय अंतर क्षेत्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताः 2019-20 संपन्न हो गया। इसका उद्घाटन संस्थान के निदेशक (तकनीकी/पीएंडडी) ए0के0 राणा एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता राणा, निदेशक (तकनीकी/ईएस) के0के0 मिश्रा की धर्मपत्नी श्रीमती ऊषा मिश्रा, मुख्य सतर्कता अधिकारी सुमीत कुमार सिन्हा, क्षेत्रीय संस्थान-3, रांची के क्षेत्रीय निदेशक मनोज कुमार एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रूपाली गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर सीएमपीडीआई के अधिकारी तथा कर्मचारीगण के अलावा जेसीसी सदस्य, सीएमओएआई के प्रतिनिधि सहितबड़ी संख्या में कला एवं संगीत प्रेमी उपस्थित रहे।

आयात पर प्रतिबंध से खाद्य तेलों में उबाल

सुशील मिश्र

पिछले कुछ महीनों से खाद्य तेलों की कीमतों में जारी तेजी और भी बढने की संभावना है। पिछले एक महीने में पाम तेल के दाम करीब 14 फीसदी बढ़ चुके हैं। देश में सोयाबीन की फसल खराब होने और रबी सीजन की तिलहन फसल आने में करीब दो महीने विलंब से लगभग सभी खाद्य तेलों का महंगा होना तय माना जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून तथा कश्मीर मामले पर मलेशिया की टिप्पणी के बाद सरकार ने कल रिफाइंड पाम तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। घरेलू बाजार में आज पाम तेल की कीमत बढ़कर 890 रुपये प्रति 10 किलो पर पहुंच गई। पिछले एक महीने में रिफाइंड पाम तेल के भाव 13.7 फीसदी, तीन महीने में 40 फीसदी और अक्टूबर से अभी तक करीब 43 फीसदी बढ़ चुके हैं। पाम तेल के साथ दूसरे खाद्य तेलों के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। पिछले एक महीने में मूंगफली तेल 9.2 फीसदी बढ़कर 1,130 रुपये प्रति 10 किलो, सूरजमूखी तेल 10.4 फीसदी बढ़कर 925 रुपये प्रति 10 किलो, सोयाबीन तेल 9.6 फीसदी बढ़कर 910 रुपये प्रति 10 किलो और सरसों तेल करीब 9 फीसदी बढ़कर 980 रुपये प्रति 10 किलो पहुंच गए हैं।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के मुताबिक रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज्ड पाम तेल और रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज्ड पामोलिन तेल की आयात नीति में संशोधन किया गया है। इन तेलों के आयात को मुक्त श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि इन तेलों के आयात के लिए अब आयातकों को सरकार से अनुमति लेनी होगी अथवा इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि देश में हर साल डेढ़ करोड़ टन तक खाद्य तेलों का आयात किया जाता है जिसमें सबसे अधिक मात्रा पाम तेल की है। इंडोनेशिया और मलेशिया से सबसे ज्यादा 90 लाख टन पाम तेल का आयात किया जाता है, जबकि शेष 60 लाख टन सोयाबीन और सूरजमुखी तेल का आयात किया जाता है। कारोबारियों के अनुसार 30 प्रतिशत पाम तेल का आयात मलेशिया से जबकि 70 प्रतिशत का आयात इंडोनेशिया से होता है।

पाम तेल आयात पर प्रतिबंध के अलावा घरेलू कारण भी खाद्य तेलों में तेजी लाने वाले हैं। चालू फसल सीजन में भारी बारिश से सोयाबीन की 15-30 प्रतिशत फसल बरबाद होने की आशंका है जिसका असर उत्पादन पर पड़ेगा। कमोडिटी फर्मों की रिपोर्ट के मुताबिक सोयाबीन उत्पादक प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश में इस साल 85 लाख टन सोयाबीन के उत्पादन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 100 लाख टन से अधिक उत्पादन हुआ था। मांग बढने और आयात प्रतिबंध के कारण इंदौर में सोयाबीन की कीमतें चार साल के ऊपरी स्तर पर चल रही हैं। रबी सीजन की प्रमुख तिलहन फसल सरसों की बाजार में आपूर्ति फिलहाल कम है। हालांकि कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू रबी सीजन में तिलहन फसलों का रकबा पिछले साल से कुछ अधिक हो चुका है।

चालू सीजन में तिलहन फसलों का रकबा 75.72 लाख हेक्टेयर हो चुका है जबकि पिछले साल इस समय तक 75.71 लाख हेक्टेयर था। कारोबारियों के मुताबिक ठंड के मौसम में मांग के मुताबिक आपूर्ति कम होने से कीमतें बढने के आसार हैं। प्रतिबंध पर उद्योग जगत का कहना है कि इससे उनकी रिफाइंड क्षमता का इस्तेमाल बढ़ेगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

एसोचैम की वन डे नेशनल समिट होटल होलिडे होम में संपन्न

बाबूलाल मरांडी भी हुये शामिल

रांची : सीएसआर कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (उरफ), जब प्रभावी रूप से लागू की जाती है, तो राज्य और देश के "समावेशी और समान विकास" में मदद करती है। भारत सरकार ने सक्रिय कदम उठाते हुए नई कंपनी अधिनियम में उरफनियम पेश किए हैं। जिसके तहत, कंपनियों को अपने लाभ का 2% समाज की भलाई के लिए खर्च करने के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार उद्योग और समाज दोनों के लिए एक जीत की स्थिति पैदा करना। । इस पृष्ठभूमि में, ASSOCHAM ने भारत के उद्योग और वाणिज्य के सर्वोच्च निकाय ने "वन डे नेशनल समिट - कम- अवाड्र्स ऑन सीएसआर - 2019, कार्यक्रम शुक्रवार, 17 जनवरी 2020 को होटल हॉलिडे होम, रांची में आयोजित किया। क्षेत्रीय निदेशक, ASSOCHM ने स्वागत भाषण दिया कृपा नंद झा (आईएएस निदेशक, उद्योग विभाग) ने कहा कि सीएसआर मुख्य उद्देश्य राज्य के साथ-साथ देश का भी कल्याण करना है। उन्होंने राजस्व सृजन, ग्रामीण क्षेत्र के निर्यात क्षेत्र के विकास से संबंधित योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। सुप्रियो भट्टाचार्य (महासचिव और केंद्र प्रवक्ता, जेएमएम) ने झारखंड के पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए सीएसआर फंड के उपयोग पर जोर दिया। मिथलेश ठाकुर (विधायक-घरवा, झारखंड) इन क्षेत्रों की बेहतरी के लिए स्वास्थ्य बीमा, कुपोषण, पेयजल, शिक्षा आदि जैसी बुनियादी समस्याओं और वर्तमान सरकार की ओर से वादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बाबु लाल मरांडी ने सभी पुरस्कार विजेताओं को उनके अच्छे काम के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि कंपनियों को गरीब छात्र शिक्षा पर सीएसआर की अधिक गतिविधियां करनी चाहिए।

फोटो न्यूज

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी है पर्यावरण की चिंता। तभी तो वह भी पेड़ लगा रहे हैं।

कांके रोड मुख्यमंत्री आवास के सामने वर्षों से अपने हालात पर रोता सड़क

अफगानिस्तान की बामियान घाटी पर जलवायु परिवर्तन की मार

एजेंसियां : बामियान घाटी एक नई चुनौती से जूझ रही है. यह चुनौती ना तालिबान से है और ना ही जिहादियों से बल्कि जलवायु परिवर्तन से है. गुफाओं और सांस्कृतिक विरासतों पर भूमि कटाव का खतरा बढ़ गया है.

अफगानिस्तान के बामियान प्रांत के पुरातात्त्विक खजाने को पहले जिहादियों ने बम से उड़ाया और उसके बाद बची कुछ अहम चीजें चोर चुरा ले गए. अब यह नई चुनौती का सामने कर रहे हैं और वह है जलवायु परिवर्तन. लंबे समय तक युद्ध झेल चुके अफगानिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि वह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बहुत काम कर पाए. ऐतिहासिक विरासत को बचाना उसके लिए बड़ी चुनौती है. सन 2001 में बामियान प्रांत में पहाड़ियों में उकेरी गईं बुद्ध की विशाल प्रतिमाओं को तालिबान ने तबाह कर दिया था. बुतपरस्ती को मिटाने के नाम पर 2001 में तालिबान शासन की ओर से टैंकों, रॉकेटों और डायनामाइट से विशाल मूर्तियों पर हमला किया गया. हिन्दूकुश पर्वतमाला के बीच में बसी बामियान घाटी में दशकों और सदियों पुरानी बुद्ध की मूर्तियां तबाह होने के बाद आज भी कई गुफाओं में मंदिर, मठ और बुद्ध की पेंटिंग मौजूद हैं.

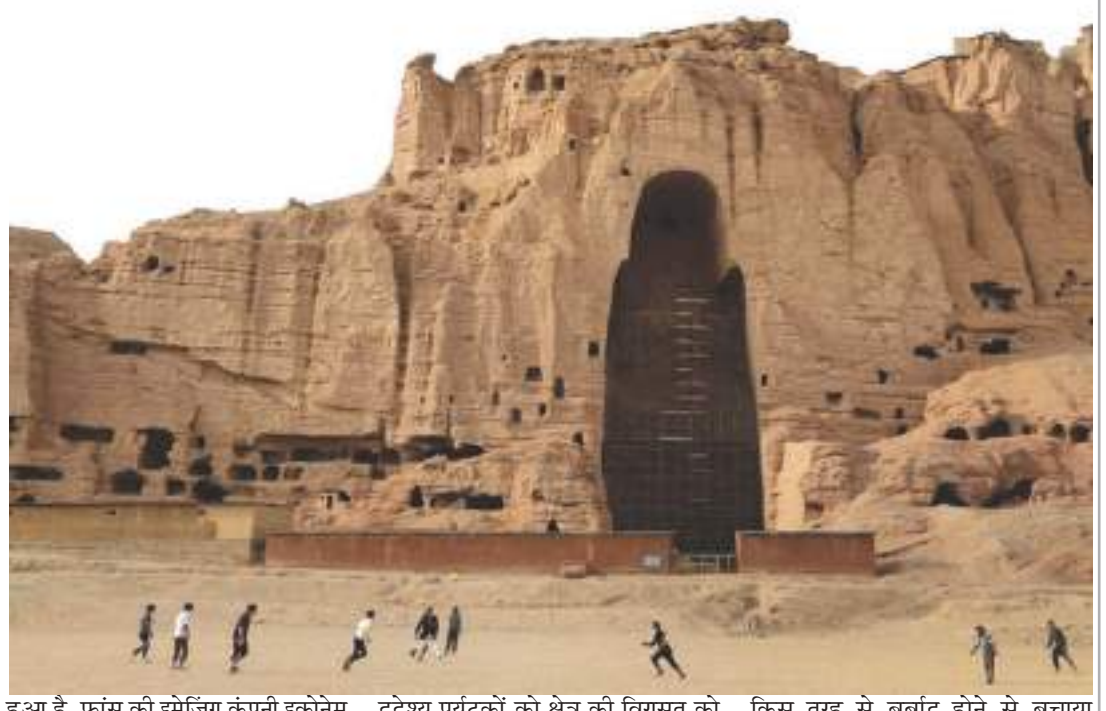

विशेषज्ञों का कहना है कि पहले सूखा और उसके बाद भारी बारिश और वसंत के मौसम में बर्फ का अत्याधिक पिघलना ऐतिहासिक कला और वास्तुकला के लिए विनाशकारी जोखिम पैदा कर रहे हैं. 2016 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में अफगान अधिकारियों को ढांचे के "गिरने और उसके गंभीर कटाव" को लेकर चेतावनी दी गई थी. रिपोर्ट में इसे सीधे जलवायु परिवर्तन से जोड़ा गया था. अफगानिस्तान में फ्रांसीसी पुरातात्त्विक प्रतिनिधिमंडल के निदेशक फिलिप मार्की के मुताबिक, "कटाव की प्रक्रिया बहुत तेज है. बारिश अधिक विनाशकारी है और हवा से होने वाला कटाव शक्तिशाली होता है. जिस वजह से स्थल को बहुत नुकसान हो रहा है." मार्की ने इस क्षेत्र में दशकों तक काम किया है और उन्हें क्षेत्र के बारे में बहुत अनुभव है. वह बताते हैं कि अफगानिस्तान भूविज्ञान के लिहाज से बहुत नाजुक है, खासतौर पर पेड़ों की कटाई के कारण वनस्पति का क्षेत्र कम

हुआ है. फ्रांस की इमेजिंग कंपनी इकोनेम का कहना है कि कटाव के कारण शार-ए-जोहक की हालत बहुत ही नाजुक है और पिछले तीस सालों में स्थिति और खराब हुई है. उत्तरी बामियान के साइ-खंड जिले के 21 साल के बाकी गुलामी के मुताबिक जलवायु परिवर्तन इलाके के लोगों के लिए एक हकीकत है जिसका सामना वह लंबे समय से कर रहे हैं. गुलामी कहते हैं, "मौसम बदल रहा है. गर्मी के दिन बहुत गर्म होते हैं और सर्दी बहुत पड़ती है." इसी इलाके में कभी बुद्ध की दो विशाल मूर्तियां हुआ करती थी. तालिबान ने मूर्ति को नष्ट करने का कारण उनका गैर इस्लामी होना बताया था. इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए ये प्रतिमाएं बरसों तक उनकी जिंदगी का हिस्सा रहीं. इलाके के लोग समाचार एजेंसी एएफपी से बात करते हुए उसके इतिहास से खुद को जोड़ते हुए गर्व करते हैं.

गुम होती एक विरासत

खाली गुफाओं से पर्यटक सांस्कृतिक केंद्र देख सकते हैं, जिसका निर्माण 2015 में शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक वह पूरा नहीं हो पाया है. केंद्र का उद्देश्य पर्यटकों को क्षेत्र की विरासत को संरक्षित करने की तत्काल जरूरत के बारे में बताना है. बामियान यूनिवर्सिटी में पुरातत्व विभाग के निदेशक अली रजा मुश्फिक कहते हैं, "अगर लोग बिना जानकारी के साइट देखते हैं तो इसका कोई लाभ नहीं है." साथ ही वह शिकायत करते हैं कि फंड की कमी के कारण कई लोग अंधकार में हैं जिनमें उनके छात्र भी शामिल हैं, जिनके पास किताबें तक नहीं है. पुरातत्त्वविद भी मानते हैं कि "कटाव बढ़ रहा है" लेकिन उनके मुताबिक असली खतरा "साइट पर मानव प्रभाव" से हो रहा है जिनमें लूट की घटनाएं भी शामिल हैं जो अफगानिस्तान में बहुत हो रही है.

इन सब घटनाओं से निपटने के लिए शार-ए घोलघोला किले और अन्य अहम साइटों पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. इलाके से बारूदी सुरंगों के हटाए जाने के कारण हाल के सालों में कई हजारों लोग यहां आए लेकिन पर्यटकों की संख्या बढ़ने से जमीनी हालात बदलने में मदद नहीं मिली है. मुश्फिक कहते हैं, "हमें स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू करनी होगी, उन्हें सिखाना होगा कि स्थल को किस तरह से बर्बाद होने से बचाया जाए." साथ ही मुश्फिक बताते हैं कि कुछ स्थानीय लोग ऐतिहासिक स्थलों का इस्तेमाल चारा रखने और जानवरों को बांधने के लिए करते हैं.

बुद्ध की गुफा से कुछ ही दूरी पर रहने वाले 37 साल के अमानुल्लाह कहते हैं कि उनके परिवार ने वहीं पास की एक गुफा को अपना ठिकाना बना लिया है. ऐसा करने वाला केवल उनका परिवार नहीं है बल्कि कई अन्य गरीब परिवारों ने प्राचीन कलाकृतियों और ऐतिहासिक ढांचे के भीतर आश्रय ले रखे हैं. अमानुल्लाह कहते हैं, "यहां करीब 18 परिवार हैं. हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है. अगर हमें मकान मिल जाता है तो हम यहां से चले जाएंगे."

हालांकि मार्की के अमपसार इन धरोहरों को सबसे बड़ा खतरा स्थानीय लोगों या चोरों से नहीं बल्कि कटाव से है. कटाव के प्रभावों और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अफगानिस्तान को अरबों डॉलर खर्च करने होंगे, लेकिन युद्धग्रस्त देश में इस तरह के बोझ उठाने की क्षमता बहुत कम है। ●

सर्दियों में मुंह से क्यों निकलती है भाप?

सर्दियों में हमारे मुंह से भाप निकलने लगती है. लेकिन जब हम घर के अंदर होते हैं तो भाप निकलती नहीं दिखती. क्या शरीर में पानी गर्म होता रहता है जिसकी भाप निकलती है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, आइए जानते हैं. सर्दियों के मौसम में हमारे मुंह से भाप क्यों निकलने लगती है? क्या हमारे शरीर में हमेशा भाप बनती रहती है? अगर ऐसा है तो गर्मियों में हमें भाप निकलती क्यों नहीं दिखाई देती? क्या जानवरों के मुंह से भी सर्दी में भाप निकलती है? ये सारे सवाल आपके मन में भी आते होंगे. सर्दी आते ही हर किसी के मुंह से भाप निकलती दिखाई देती है. इस भाप के पीछे की वजह बड़ी सामान्य सी होती है. जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाई ऑक्साइड निकलती है. लेकिन यह पूरा सच नहीं है. सांस छोड़ते समय फेफड़ों से कार्बन डाई ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन, कम मात्रा में ऑक्सीजन, आर्गन और नमी भी शामिल होती है. यह नमी शरीर में कहां से आती है? क्योंकि हमारा मुंह और फेफड़े नम रहते है. इसलिए हर सांस के साथ थोड़ी मात्रा में नमी भाप के रूप में शरीर से बाहर निकलती है. जब शरीर में नमी यानी जल की मात्रा बढ़ती है तो ये पसीने और मूत्र में निकल जाती है .पानी तीनों अवस्थाओं में होता है. ठोस, द्रव और गैस. ठोस होने पर पानी बर्फ, द्रव होने पर जल या पानी और गैसीय अवस्था में होने पर भाप कहलाता है. बर्फ में एच2ओ के अणु मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं. द्रव अवस्था में थोड़ी कम मजबूती और गैसीय अवस्था में और भी कम मजबूती के साथ ये आपस में जुड़े होते हैं. गैसीय अवस्था में एच2ओ के अणुओं में ऊर्जा ज्यादा होती है जिससे ये गतिक अवस्था में होते हैं. मानव शरीर का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है. ऐसे में जब बाहर का तापमान कम होता है और हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो शरीर से निकलने वाली नमी के अणु अपनी ऊर्जा तेजी से खोने लगते हैं और पास–पास आ जाते हैं. इससे भाप द्रव या ठोस अवस्था में बदलने लगती है. ये भाप छोटी–छोटी पानी की बूंदों में होती है. अगर तापमान शून्य से ज्यादा नीचे हो तो मुंह से निकलने वाली भाप बर्फ में बदलने लगती है. ऐसा अक्सर तब होता है जब तापमान सात डिग्री सेल्सियस से कम होता है. विज्ञान के मुताबिक गैस में अणु दूर दूर, द्रव में थोड़े पास और ठोस में एकदम चिपके रहते हैं. भाप द्रव और गैस के बीच की अवस्था है. इसे द्रवित गैस कहा जा सकता है.

जब बाहर के तापमान में गर्मी होती है तब नमी शरीर से बाहर निकलती है तो गैसीय अवस्था में ही रहती है. क्योंकि इसके अणुओं की गतिक ऊर्जा कम नहीं होती है और वे दूर दूर ही रहते हैं. इस वजह से ये भाप या पानी की बूंदों में नहीं बदल पाते. लेकिन जब बाहर का तापमान कम होता है तब निकलने वाले नमी और गैस अपनी गतिक ऊर्जा तेजी से खोते हैं और उसके अणु पास पास आने लगते हैं. ये अणु पास–पास आकर भाप बन जाते हैं.

भारत सरकार के आइकैट संस्था द्वारा अधिकृत बस बॉडी का लोकार्पण

संवाददाता

रांची : भारत सरकार के मानक आइकैट द्वारा अधिकृत बजरा इटकी रोड में स्थित मां तारिणी कोच बॉडी बिल्डर ने पहला बस बॉडी बना कर झारखंड रांची में शुरूआत की है। इस बॉडी का लोकार्पण नारिया फोड़ कर रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ ने किया। मां तारिणी कोच बॉडी बिल्डर के निदेशक संतोष प्रसाद गुप्ता ने बताया कि इस नवनिर्मित बस बॉडी को भारत सरकारके आइकैट के निर्धारित मानक को देखते हुये कुशल कारीगरों द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। इस वाहन में सुरक्षा के साथ साथ सारी सुविधायें उपलब्ध हैं। इस मौके पद विशिष्ट अतिथि रांची विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, पंडरा अध्यक्ष सुबेश पांडेय, छात्र क्लब ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष शिव किशोर शर्मा परिवहन विभाग के अधिवक्ता सी एम के त्रिपाठी व अन्य मौजूद थे।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

● Repair your laptop with 3-month warranty.

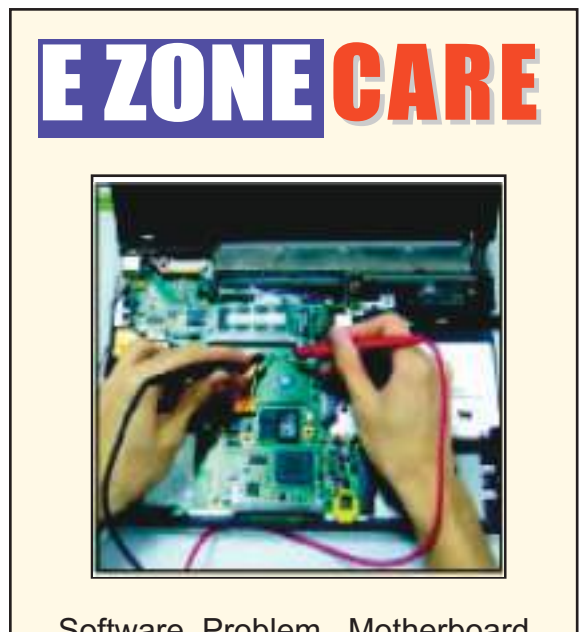

info@ezonecare.in, ezonecare.in

Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, ranchi

93108 96575, 70047 69511

Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm

SUNDAY CLOSED

आज भी कोयले पर क्यों चल रहे हैं संयंत्र ?

एजेंसियां : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोयले से चलने वाले 11 संयंत्रों को उत्सर्जन को कम करने वाले उपकरण लगाने के लिए कहा गया था. इसकी अंतिम तिथि बीत चुकी है और ये संयंत्र वैसे के वैसे चल रहे हैं. साल 2019 के खत्म होने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चल रहे 11 संयंत्र फिर से समीक्षा के घेरे में आ गए हैं. कोयले से चलने वाले इन संयंत्रों को चेतावनी दी गई थी कि अगर इन्होंने साल के अंत तक सल्फर ऑक्साइड से होने वाले उत्सर्जन को कम करने वाले उपकरण नहीं लगाए तो इन्हें बंद कर दिया जाएगा. लेकिन नए साल की शुरुआत हो चुकी है और ये संयंत्र अभी तक वैसे ही चल रहे हैं. नई दिल्ली के आस पास बिजली के संयंत्र चलाने वाली कंपनियों के कम से कम तीन वरिष्ठ अधिकारियों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि उन्हें अभी तक इस बारे में कोई निर्देश नहीं मिले हैं कि उपकरण लगाए बिना वो पहले की ही तरह संयंत्रों को चला सकते हैं या नहीं. इन 11 संयंत्रों में से सिर्फ एक ने उपकरण लगवाया है.

पहले इन संयंत्रों को बंद करने की आखिरी तिथि 31 दिसंबर 2017 ही थी, पर बाद में इसे आगे बढ़ा दिया गया था. इससे फेफड़ों की बीमारी पैदा करने वाले और वायु की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषण से लड़ने वाली

एजेंसियों की चुनौती बढ़ गई थी. भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने इन संयंत्रों को निर्देश ना मानने पर बंद करने की चेतावनी दी थी. अब जब आखिरी तिथि बीत चुकी है तो सीपीसीबी का अभी तक इस विषय पर कोई बयान नहीं आया है. समाचार एजेंसी के बार बार फोन करने और टेक्स्ट संदेश भेजने पर भी सीपीसीबी के अधिकारियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. पिछले महीने समाचार एजेंसी रायटर्स ने खबर दी थी की भारत में कोयले से चलने वाले ऊर्जा संयंत्रों में से आधे और कोयले से चलने वाले अन्य संयंत्रों में से 94 प्रतिशत संयंत्र आखिरी तिथि तक उत्सर्जन कम करने वाला उपकरण लगा पाने की स्थिति में नहीं लग रहे हैं. पहली जनवरी को राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता का सूचकांक "गंभीर" स्तर पर था, जैसा कि इस बारे जाड़े में अधिकतर दिनों पर रहा. यह स्वस्थ लोगों के लिए भी एक संभावित खतरा है. ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दोनों ऊर्जा संयंत्र चल रहे थे, जबकि उन्हें दी हुई 31 दिसंबर तक की मियाद खत्म हो चुकी है. पंजाब में वेदांता कंपनी की तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) की इकाइयां और रोपड़ और भटिंडा में सरकारी संयंत्र बिजली बना रहे थे.उत्तरी हरियाणा में बिजली बनाने वाली सरकारी कम्पनी एचपीजीसीएल में प्रबंधक निदेशक मोहम्मद शायिन ने बताया कि जिन इकाइयों में पहले से निर्धारित रख-रखाव चल रहा है उन्हें छोड़ कर बाकी सभी इकाइयां चल रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि एचपीजीसीएल ने केंद्रीय एजेंसियों से निवेदन किया है कि उत्सर्जन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया जाए. वेदांता और लार्सन एंड टूब्रो (एल एंड टी) जैसी निजी कंपनियों ने भी अंतिम तिथि को बढ़ाने के ही पक्ष में बात रखी.

एल एंड टी के स्वामित्व वाली नाभा पावर ने कहा कि "सीपीसीबी द्वारा अंतिम तिथि बढ़ने में हुई देर की वजह से उसे अपनी दोनों इकाइयां बंद करने पर मजबूर होना पड़ रहा है." वेदांता ने भरोसा जताया है कि एजेंसियां "विचारशील रुख अपनाएंगी." कंपनी का यह भी कहना था, "अगर हमें सीपीसीबी या पर्यावरण मंत्रालय से निर्देश आएंगे तो हम संयंत्र को बंद कर देंगे।

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN/2019/78094, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।